जनसत्ता

असुरक्षित मिग

भारत के वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने एक बार फिर मिग-21 विमानों के इस्तेमाल को लेकर जो चिंता व्यक्त की है, उससे यह साफ है कि ये विमान अब किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इसीलिए उन्हें यह कहना पड़ा है कि इतनी पुरानी तो हम कार भी नहीं चलाते हैं जितने पुराने मिग विमान उड़ा रहे हैं। वायुसेना अध्यक्ष की यह फिक्र वाकई जायज है, क्योंकि शायद ही कोई महीना बीतता हो जब मिग के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई खबर न आ जाती हो। पिछले कुछ सालों में मिग विमानों के हादसे जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे यह सवाल उठना लाजिमी है कि कब तक हमारे लड़ाकू पायलट अपनी जान जोखिम में डाल कर इन विमानों को उड़ाते रहेंगे। लेकिन वायुसेना में अभी भी जिस बड़ी संख्या में, भले ही मजबूरी में इन विमानों का उपयोग किया जा रहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है। हकीकत यह है कि आज भी मिग-21 विमान ही वायुसेना की रीढ़ बने हुए हैं। सिर्फ भारत ही दुनिया में एकमात्र देश है जो पचास साल पुराने मिग विमानों के दम पर अपनी वायुसेना को धकेले जा रहा है।

वायुसेना प्रमुख पहले भी मिग विमानों के पुराने पड़ने और वायुसेना के आधुनिकीकरण का मसला उठाते रहे हैं। लेकिन वायुसेना की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उसके पास पर्याप्त लड़ाकू विमान नहीं हैं। ऐसे में मिग विमानों से ही काम चलाना पड़ रहा है चाहे पायलटों का प्रशिक्षण हो या फिर सैन्य अभियान। पिछले कुछ सालों में हुए मिग हादसों में भारत ने कई जांबाज पायलटों का खोया है। पिछले चार दशकों में पांच सौ से ज्यादा मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और दो सौ से ज्यादा पायलट मारे जा चुके हैं। पायलटों का मारा जाना वायुसेना के लिए मिग खोने से भी ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। हालांकि वायुसेना प्रमुख कह चुके हैं कि रफाल विमान मिलने के बाद मिग विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। रफाल विमानों की पहली खेप भारत को अगले महीने मिलेगी और अगले तीन साल में छत्तीस रफाल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में होंगे। इस तरह पहले चरण में 2022 तक मिग-21 विमान हटाए जाएंगे और 2030 तक मिग-27 और मिग-29 विमान भी हटा दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2030 तक वायुसेना पुराने मिग विमानों का ही उपयोग करती रहेगी और हम अपने लड़ाकू पायलटों को खोते रहेंगे?

आज दुनिया के बड़े देश अंतरिक्ष युद्ध की तैयारियों में लगे हैं। हाल में भारत ने अंतरिक्ष में निशाना साधने में कामयाबी हासिल की है। पर विडंबना यह है कि एक ओर हम अंतरिक्ष की ताकत बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारी वायुसेना के पास जरूरत भर के भी विमान नहीं हैं। अभी वायुसेना को युद्धक विमानों के बयालीस बेड़ों (स्क्वाड्रन) की जरूरत है, जबकि उसके पास सिर्फ इकतीस बेड़े ही हैं और वे भी पुराने विमानों के। हालांकि पिछले एक दशक में मिग विमानों को बायसन मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने का काम तो हुआ है और इनमें राडार, दिशासूचक प्रणाली आदि को बेहतर किया गया है। लेकिन पुराने विमानों को अद्यतन करने भर से विमान सुरक्षित हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? रक्षा विशेषज्ञ भी मिग विमानों को उन्नत बना कर काम में लेने पर इसलिए चिंता जताते रहे हैं कि विमानों की भी एक उम्र होती है और उसके बाद वे काम लायक नहीं रह जाते हैं। ऐसे में वायुसेनाध्यक्ष का यह कहना कि इतनी पुरानी तो कोई कार भी नहीं चलाता है जितने पुराने हम विमान उड़ा रहे हैं, क्या गलत है!

अंधविश्वास की जकड़न

इक्कीसवीं सदी के इस दौर में हम वैज्ञानिक उपलब्धियों के जरिए मंगल और चांद पर शोध की जो नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, उसे दुनिया भर में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। मगर इसी के समांतर जब अंधविश्वास में डूबी गतिविधियों की खबर मिलती है तो निश्चित रूप से यह बेहद अफसोस की बात है। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में दो मृत भाइयों के पुनर्जीवन की इच्छा से जिस तरह के अंधविश्वास का खुला प्रदर्शन देखा गया, उससे फिर यही साफ हुआ है कि अभी इस मोर्चे पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गौरतलब है कि इंदौर जिला मुख्यालय से करीब तीस किलोमीटर दूर तालाब में डूब गए दो भाइयों को निकाल कर सांवेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। वहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। लेकिन परिजनों ने चूंकि सोशल मीडिया पर कहीं पढ़ा था कि मृतक के शरीर को अगर नमक से ढक कर रखा जाए तो वह फिर से जी उठता है, इसलिए उन्होंने डॉक्टरों की राय और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को किनारे कर दिया और शवों को नमक से ढक दिया।

सवाल है कि आखिर किन वजहों से मृतक के परिजनों के साथ-साथ वहां के स्थानीय निवासियों में से किसी को इस बेमानी धारणा पर सवाल उठाना और उसे महज अंधविश्वास बताना जरूरी नहीं लगा। खबरों के मुताबिक ग्रामीणों की भीड़ के दबाव में स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद डॉक्टर भी लाचार थे और वे भी इस घटना को रोक नहीं सके। जैसा कि स्वाभाविक था, अफवाह पर आधारित एक बेमानी कवायद नाकाम हुई और आखिरकार मृत भाइयों के परिजनों और गांव वालों को सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा कि किसी मर चुके व्यक्ति को अंधविश्वास के सहारे जिंदा नहीं किया जा सकता। इतना तय है कि वहां कुछ लोग पढ़े-लिखे जरूर होंगे। लेकिन उस पढ़ाई-लिखाई का क्या फायदा जो सामान्य से अंधविश्वास पर आधारित धारणाओं को तोड़ने में भी मददगार साबित नहीं हो सके। ऐसे लोगों के सोचने-समझने के स्तर और उसके लिए जिम्मेदार स्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी कल्पना या अंधविश्वास को इसलिए सही मान लेता है कि वह सोशल मीडिया पर कहीं लिखा हुआ था।

इस समूची घटना की विडंबना यह भी है कि जो सोशल मीडिया तकनीकी विकास और विज्ञान की उपलब्धियों का एक औजार माना जाता है, वही आज अंधविश्वास को फैलाने का जरिया भी बन रहा है। दरअसल, हमारे देश में विज्ञान विषयों की पढ़ाई तो कराई जाती है लेकिन शायद ही कहीं वैज्ञानिक चेतना के विकास और उसे मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। यह बेवजह नहीं है कि कई बार बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों के मौके पर भी आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ाने वाली गतिविधियां देखी जाती हैं। जबकि संविधान में मौजूद अनुच्छेद 51-ए (एच) के तहत मानवीयता, वैज्ञानिक चेतना और तार्किक सोच को बढ़ावा देने के लिए सरकार और समाज की जिम्मेदारी तय की गई है। सवाल है कि संविधान में दर्ज व्यवस्था के बावजूद समाज में अंधविश्वास पर आधारित गतिविधियां और उसे फैलाने की कोशिशें कैसे बदस्तूर जारी रहती हैं! अंधविश्वास पर आधारित पिछड़ेपन और अफसोसनाक परंपराओं को बनाए रख कर क्या कोई भी समाज केवल साक्षरता दर में इजाफे के बूते और अक्सर बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है? जरूरत इस बात की है कि वक्त के साथ समाज में अंधविश्वासों को दूर करने के लिए इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए और वैज्ञानिक चेतना के विकास के साथ-साथ उसे मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए।

कल्पमेधा

उन व्यक्तियों से मैं महानतम पद भी स्वीकार नहीं करूंगा, जो न तो स्वप्न लेते हैं और न ही इच्छाएं पालते हैं।

- खलील जिब्रान

चीन का संकट बना हांगकांग

संजीव पांडेय

चीन से यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि वह हांगकांग में 'एक देश दो व्यवस्था' को खत्म करने पर क्यों तुला है? हांगकांग के लोगों को मिली स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है? हांगकांग के लोगों को उस न्यायिक व्यवस्था में लाने की कोशिश क्यों हो रही है जो एक पार्टी के नियंत्रण में है? चीन ने हांगकांग के लोगों से लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर वादे किए थे, उसे पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया?

चीन को इस वक्त फिर एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो महीनों से हांगकांग की सड़कों पर जिस तरह से जनसमूह उमड़ रहा है उससे चीन के हाथ-पैर फूलने लगे हैं। चीनी सरकार के खिलाफ इस विद्रोह का मूल कारण कई अपराधों में संलिप्त अपराधियों को प्रत्यर्पित करने की अनुमति देने वाला विधेयक है जिसका हांगकांग में जोरदार विरोध हो रहा है। हांगकांग सरकार के इस प्रत्यर्पण विधेयक के पीछे चीन है। दरअसल, चीन और ताइवान के साथ हांगकांग की अभी तक कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। प्रस्तावित प्रत्यर्पण विधेयक के पारित होने के बाद हांगकांग, ताइवान और चीन के बीच अपराधियों को प्रत्यर्पित करने की अनुमति मिल जाएगी।

हांगकांग के लोग इसे अपने देश की स्वायत्तता खत्म करने के कदम के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए दो महीने से इसका जोरदार विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह विधेयक उस चीनी न्यायिक व्यवस्था में स्थानीय लोगों को भेजने का रास्ता है जो एक राजनीतिक पार्टी के नियंत्रण में है। हालांकि विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि प्रत्यर्पण बिल से बड़े वित्तीय और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि भारी विरोध के बाद हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने फिलहाल इस विधेयक को निलंबित कर दिया है, लेकिन इसे वापस नहीं लिया है। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों पर चीनी सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अमेरिकी के साथ व्यापार युद्ध के मोर्चे पर फंसी चीन अगर हांगकांग में सैन्य कार्रवाई जैसा कदम उठाती है तो इससे उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।

हांगकांग के आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया है। पहले आंदोलन में छात्र ही शामिल थे। लेकिन बाद में छात्र संघ, सामाजिक कार्यकर्ता, यूनियन कार्यकर्ता, अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मचारी और शिक्षक भी आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन को पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने हांगकांग सरकार के प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि विधेयक की आलोचना की है। ब्रिटेन ने भी हांगकांग के आंदोलनकारियों के प्रति समर्थन जताया है। ब्रिटेन का समर्थन महत्त्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हांगकांग उसका उपनिवेश रहा है। पश्चिमी देशों का भी तर्क है कि प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून लागू होने के बाद चीन की न्यायिक व्यवस्था में हांगकांग के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हांगकांग एशिया का एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। यही कारण है कि इस आंदोलन को हवा दे पश्चिमी देश चीन को दबाव में लाना चाहते हैं ताकि अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रख सकें। हांगकांग का आंदोलन ऐसे वक्त में तेज हुआ है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध चरम पर है। चीन पर इस व्यापार युद्ध का असर दिखने भी लगा है। इस साल अप्रैल-जून तिमाही में चीन की विकास दर पिछले सत्ताईस साल में सबसे कम रही है।

हांगकांग के आंदोलन का असर चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वांगडोंग-हांगकांग-मकाऊ बृहतर खाड़ी क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इस प्रस्तावित बृहतर खाड़ी क्षेत्र से चीन, हांगकांग और मकाऊ की अर्थव्यवस्था को भारी लाभ मिलेगा। चीन की योजना के मुताबिक बृहतर खाड़ी क्षेत्र के विकास के तहत हांगकांग, मकाऊ और ग्वांगडोंग प्रांत को एकीकृत करने की योजना है। इससे पूरे क्षेत्र में और विकास होगा। चीन को शक है कि इस योजना को नुकसान पहुंचाने का खेल भी पश्चिमी ताकतें कर रही हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि हांगकांग के आंदोलन में शामिल लोग परेशान हैं। हांगकांग की अर्थव्यवस्था उन्हें एक बेहतर जिंदगी नहीं दे रही है। पढ़े-लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से पर्याप्त वेतन वाली नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार के अवसर तो उपलब्ध हैं लेकिन उम्मीद के मुताबिक वेतन नहीं है। जो वेतन इस समय हांगकांग में लोगों को मिल रहा है उससे युवा अपने लिए एक घर नहीं खरीद सकता है। चीन के मीडिया ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार आंदोलन में शामिल युवाओं के सामने बेहतर वेतन और रोजगार एक समस्या है। आंदोलन तेज होने के बाद हांगकांग की अर्थव्यवस्था पर भी चोट पहुंची है। व्यापार ठप पड़ा है। पर्यटन से लेकर खुदरा कारोबार को नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, हांगकांग शेयर बाजार को भारी नुकसान हुआ है। अभी

तक हांगकांग के शेयर बाजार को पांच सौ अरब डालर का नुकसान हो चुका है। संपतियों की बिक्री में पैंतीस फीसद तक की गिरावट आई है।

चीन एक तरह से कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। हाल में भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर देने के बाद चीन भी भड़का हुआ है। चीन की नाराजगी लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने को लेकर है। अभी तक लद्दाख को भी जम्मू-कश्मीर का हिस्सा होने के कारण विशेष दर्जा मिला हुआ था। चीन की नजरों में लद्दाख विवादास्पद क्षेत्र है। इसकी सीमा अक्साइ चीन से मिलती है जिस पर भारत का दावा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन ने भारी निवेश कर रखा है। यहां पर चीन बिजली परियोजनाएं लगा रहा है। सड़कों का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। जाहिर है चीन कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने को लेकर चीन की नाराजगी और नीतियों का भारी विरोधाभास हांगकांग में नजर आता है। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर चिंता जता रहा चीन हांगकांग के विशेष दर्जे को समाप्त करने की योजना बना रहा है। हांगकांग को लेकर चीन ने जो वादा वहां के लोगों से किया था, उसे आज तक पूरा नहीं किया। और तो और लोकतांत्रिक तरीके से हांगकांग की स्वायत्तता को बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे युवाओं को चीन अब आतंकी घोषित करने की योजना बना रहा है। हांगकांग के आंदोलन का सैन्य दमन की धमकी भी दे रहा है।

चीन से यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि वह हांगकांग में 'एक देश दो व्यवस्था' को खत्म करने पर क्यों तुला है? हांगकांग के लोगों को मिली स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है? हांगकांग के लोगों को उस न्यायिक व्यवस्था में लाने की कोशिश क्यों हो रही है जो एक पार्टी के नियंत्रण में है? चीन ने हांगकांग के लोगों से लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर वादे किए थे, उसे पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया? हांगकांग के लोग पश्चिमी देशों की तर्ज पर लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन चीन ने इसे मंजूर नहीं किया। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी को सीधे हांगकांग की जनता द्वारा चुना जाना चीन को मंजूर नहीं है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा मुखिया या मुख्य कार्यकारी का चुनाव एक चुनाव समिति करती है जिसमें सिर्फ बारह सौ सदस्य हैं।

सच्चाई तो यही है कि भारतीय कूटनीति चीन के दबाव में है। ओसाका में हाल ही में हुए जी-20 की बैठक में हांगकांग के आंदोलनकारी नेताओं ने जी-20 के नेताओं को ज्ञापन देकर हांगकांग के आंदोलन के लिए समर्थन मांगा था। आंदोलनकारियों ने ओसाका की बैठक में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों को ज्ञापन देकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने आंदोलनकारियों का पक्ष रखने की अपील की थी। दिलचस्प बात यह थी कि भारत और इंडोनेशिया ने आंदोलनकारी नेताओं का ज्ञापन स्वीकार नहीं किया। जबकि बाकी देशों के नेताओं ने आंदोलनकारी नेताओं का ज्ञापन भी स्वीकार किया और चीन के सामने हांगकांग के आंदोलनकारियों का मुद्दा भी उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हांगकांग के आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर चिंता जताई।

शब्द के संदर्भ

राजकुमारी

दुनिया मेरे आगे

जड़ता, रूढ़िवादिता, स्थिरता जैसी नकारात्मक मानसिक स्थितियों के विखंडित होने का समय तभी आता है, जब आप वैचारिकता का दामन कस कर पकड़ते हैं और चिंतन की ओर अग्रसर होते हैं। किसी मसले पर होने वाली बात या फिर उठने वाले सवाल पर तपाक से पत्थर या फिर फूल से शब्द बना कर फेंकना और उसे लपकना मुश्किल हो जाता है। यों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के न जाने कितने शब्द टकराते हैं। लेकिन मैं आमतौर पर बोले जाने वाले एक शब्द 'कपल' की बात साझा करना चाहती हूं। इस पर विचार करते हुए यही लगा कि आखिर कब हम जंग लगी बुद्धि को सफाई अभियान के तहत लाकर कूड़ा बाहर फेंकेंगे। यहां बात वैसे व्यक्ति की है जो अंग्रेजियत से नाता तो जोड़ बैठा है, पर उसके संदर्भों को समझना जरूरी नहीं मानता। अगर जुबान पर 'ऑस्सम' या 'नाइस' न रहे तो कैसे दिखाएं 'इंग्लिश-विंग्लिश'!

खैर, जैसे ही कोई कहता है 'ब्यूटीफुल कपल' तो उससे गहरा रोमांच झलकता है। जो असल में 'कपल' हैं, वे बाग-बाग हो जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो इस शब्द के अर्थ की समझ बड़ी तुच्छता लिए है। कोई पुरुष और स्त्री एक साथ दिखे नहीं कि उसे 'कपल' मान लिया, इल्म और अदब दिमाग से फुर्र हो गया। जमाने से दिमाग के बाइस्कोप में दो विपरीतलिंगी व्यक्ति की चिपकी तस्वीरों को देख कर एक ही खयाल का वेग से आना- 'प्रेमी जोड़ा'। इससे इतर भाई-बहन, दोस्त, गुरु-शिष्या, सहकर्मी, सहपाठी- यानी सब रिश्तों पर हावी एक स्थायी विचार रिश्तों का गुड़-गोबर कर देता है। उम्र, हाव-भाव, तस्वीरों में खड़े होने का तरीका, सबको पीछे छोड़ और अक्ल को घास चरने भेज कर मंदबुद्धि लोग चलते-चलते कह जाते हैं और फिर सफाई देते हैं तस्वीर में मौजूद लोग। सुनने वाले दोस्त हैं तो ठहाका मार कर हंस लेते हैं। तब आनंद से मन के पांव थिरकने लगते हैं जब वाकई प्रेमी ही 'कपल' होते हैं। एक दूसरे से नजदीकी सिद्ध करने के चक्कर में सार्वजनिक स्थान के खयाल से भी ऊपर उठ कर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। हाथों की अंगुली मुट्ठी में और अत्यधिक कसावट, सुंदरता में बनावट की मिलावट। यानी दो शब्द क्या-क्या न कराए! लेकिन अगर वे बहन-भाई हुए तो जिज्ञासा रखने वाले झल्ला जाते हैं, मानो जुबान जल जाए। इसके बाद तो पुरुष और स्त्री का साथ बाहर निकलना हुआ तो नियम और शर्तें लागू समझिए, वरना साथ बाहर न निकलने का ऐलान।

इस दौर में असमंजस की स्थिति बड़ी विचित्र है। लड़के-लड़कियों में बढ़ती आधुनिक भेड़चाल, खड़े होने और बैठने की बेढंगी मुद्राएं, बेलगाम व्यवहार, आम बातचीत में गाली-गलौज। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से सामान्य लोग इस प्रचलित शब्द को वरीयता देने लगे। फिर यह बार-बार उपयोग में आने लगा। शब्दों को जुबान से बाहर धकेलने का काम आमतौर पर पार्कों, भ्रमण वाले सार्वजनिक स्थानों, रेस्तरां, मेट्रो की सीढ़ियों आदि पर भी फैलता दिखता है। ऐसे युवा जिनकी जींस पैंट से लगता है कि अब निकल कर गिर जाएगी, वे किसी प्रवाह से गुजरते आसपास के माहौल से बेखबर बेफिक्र लगते रहते हैं! फिर कुछ सोच कर बोलने की गुंजाइशें खत्म ही समझिए।

धीरे-धीरे सोशल मीडिया के मंचों का विस्तार ही हो रहा है। लेकिन इस पर मौजूद दो ठीक-ठाक से दिखने वाले लोग कभी मिले हों किसी मौके पर और उनकी तस्वीरें उनकी वाल पर दिखे तो भी अनुमान से ही इस तरह के शब्द धड़ल्ले से चिपका दिए जाते हैं। ऐसा बोलने वाले बोल कर निकल जाते हैं, उसमें उलझे रहते हैं वे, जिन्होंने अपनी वाल पर तस्वीर डाली होती है। ऐसे में कई बार स्थिति बिगड़ जाने की पूरी गुंजाइश होती है। किसी की नासमझी बेवजह ही भावनात्मक रिश्तों में दरार का कारण भी बन जाती है। इसलिए बिना लगाम के 'कपल' शब्द का प्रयोग करने वाले के बजाय ऐसे लोगों के बीच मजबूत रिश्ते के लिए जरूरी है ऐतबार, समझदारी और सूझ-बूझ। समझदारी हो तो रिश्ता बच जाए और दूसरा न सुने तो बिखर भी जाए। विचारों में नजाकत बाकी होगी, तभी 'कपल' शब्द के मायने समझ सकेंगे। वरना यह शब्द नाइत्तिफाकी के कठघरे में खड़ा रहेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले एहतियात बरतना जरूरी है। इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस शब्द का सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या किस प्रकार उनके निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है।

हमने खूब सुना होगा कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। तो शब्द अपनी अर्थवत्ता खो दे, उससे पहले शब्दों का प्रयोग सही रूप में समझदारी से करने की जरूरत है। अनुचित प्रयोग किसी का अनर्थ करा दे सकता है। पहले तोला जाए, फिर बोला जाए। शब्दों का अपना सौंदर्य है जो खोने न पाए। यानी इल्तजा यह है कि 'कपल' न कहें तो भी चलेगा, मगर गलत उपयोग न करें। किसी भी शब्द का प्रयोग अपनी बुद्धिमता से करें, क्योंकि व्यक्ति और शब्दों की गरिमा, दोनों को बचाना महत्त्वपूर्ण है।

यमुना में बाढ़

हर साल बरसात के दिनों में हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़े जाने से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण यमुना का अतिक्रमण और दशकों से इसमें कचरा और गाद से भरा होना है। यही हाल देश की अन्य नदियों का भी है जिससे आसपास के इलाके हर साल बाढ़ के पानी में डूबते हैं। इस तरह की आपदा से हर साल जो नुकसान होता है, उसका कोई अनुमान भी नहीं है। आज भी सिर्फ कागजों और विज्ञापनों में तो बहुत कुछ करने और कदम उठाने के वादे और दावे किए जाते हैं मगर धरातल पर कुछ नहीं है और उसका नतीजा हर साल बाढ़ में डूबे इलाके दिखने के रूप में आता है। दुख की बात तो यह है कि इनके असली बजट का बड़ा हिस्सा तो महज विज्ञापनों पर ही खर्च कर दिया जाता है और असली काम छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए आज सबसे पहले नदियों को अतिक्रमण मुक्त करवा कर इनकी खुदाई और सफाई की अधिक जरूरत है ताकि भविष्य में इनके बाढ़ जैसे फैलाव को रोका जा सके।

● *वेद मामूरपुर, नरेला, दिल्ली*

बाढ़ और सबक

जुलाई-अगस्त का महीना देश में अत्यधिक बाढ़ लाने वाला होता है। इसके चलते कई राज्य बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। हाल में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तक में बाढ़ का भयावह मंजर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग मारे गए है, लाखों बेघर हो गए हैं, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और अरबों रुपए की क्षति हुई है। लेकिन हमारी राज्य सरकारों का हाल यह है कि वे इस समस्या से निपटने के लिए पिछली बार से कोई सबक नहीं सीखतीं। पता है कि साल में दो महीने बाढ़ से हालात खराब होते हैं फिर भी बचाव के स्थायी उपाय नहीं किए जाते।

● *अमित कुमार, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली*

पीओके भी हमारा

जब से भारत व पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बने हैं, तब से ही पाकिस्तान भेड़िया आया, भेड़िया आया की तर्ज पर कश्मीर का राग अलापता रहा है। अब राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बारी है कि 'पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पर भारत का हक है', इसे लेकर भारत माहौल बनाए रखे। जब सीधी उंगली से बात नहीं बनती है तो हमें टेढ़ी उंगली से ही अपनी बात मनवानी होगी। यह व्यावहारिक और नैतिक कदम है। अब भारत को शांति से नहीं बैठना चाहिए।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

रैगिंग या संस्कार!

इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने अपने सिर मुंडवाए और कक्षा में सिर झुका कर प्रवेश किया। सबसे ज्यादा हास्यास्पद तो यह है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली रैंगिंग की इस घटना को विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार से पूछा गया तो उन्होंने इसे 'संस्कार' बताया न कि 'रैगिंग'। पहले साल के डेढ़ सौ छात्रों का एक साथ सिर मुंडवाना, एक जैसी पोशाक पहन कर और सिर झुका कर कक्षा में प्रवेश करना कैसे मान लें कि ये मेडिकल कालेज का 'संस्कार' है ? कुलपति द्वारा यह कहना कि कोई छात्र शिकायत करता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और एंटी रैगिंग समिति उसकी जांच करेगी, साफ-साफ नजर आ रहा है कि यह मामला रैगिंग का है। सवाल तो यह है कि कौन जूनियर अपने सीनियर के खिलाफ शिकायत करके जान जोखिम में डालेगा? सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बावजूद ज्यादातर संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं आज भी जारी हैं। दुखद तो यह है कि संस्थान न तो ऐसी घटनाओं को रोकते हैं, बल्कि किसी ऐसी घटना के सामने आने पर उसे दबा दिया जाता है।

● *शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

पाक की गीदड़ भभकी

भारत के रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया है। रक्षा मंत्री ने हाल में कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नही आता है तो अब उसे उसी की भाषा में सीमा पर ही जवाब मिलेगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बेअसर कर उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिए जाने के बाद से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर वे भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चले गए। लेकिन दोनों ही जगहों पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। चीन के अलावा कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। फिलहाल देखने की बात यह है कि अब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तब उसे क्या हासिल होता है। पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर भारत ने अपना अड़ियल रवैया अपनाया तो वह उसे सबक सिखा सकता है, फिर भले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े।

● *राहुल उपाध्याय, बलिया*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बदहाल स्कूली शिक्षा

बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से बच्चों का भविष्य अधर में है। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। आज बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए कई योग्य अभ्यर्थी बैठे हैं जबकि बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। बिहार में शिक्षा सुधार न हो पाना आला अधिकारियों की भी कमी है। वे स्कूलों में केवल मध्याह्न भोजन की जांच करते हैं। बिहार की शिक्षा केवल मध्याह्न भोजन तक ही सीमित रह गई है। कई स्कूलों में तो कायदे से पढ़ाई तक नहीं हो रही, कई स्कूलों में बच्चें ही नहीं आते, जबकि कई स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी चलती है। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जो शिक्षा का केंद्र न होकर पशु-गृह और अतिक्रमण के केंद्र में तब्दील हो गए हैं। यहां विकास के लिए आवश्यक संसाधन तक नहीं है। सवाल है ऐसे में बच्चे क्या और कैसे पढ़ेंगे?

● *मनकेश्वर भट्ट, मधेपुरा*